भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2647

उत्तर देने की तारीख 24.03.2025

एमएसएमई के लिए जेडईडी प्रमाणन योजना

2647. **श्री मल्लिकार्जुन खरगेः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ऐसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट (जेडईडी) योजना के शुभारंभ के बाद से इसका प्रमाणन प्राप्त किया है, तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने एमएसएमई की स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मकता पर जेडईडी प्रमाणन के प्रभाव के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जेडईडी योजना में विशेष रूप से छोटे उद्यमों के बीच एमएसएमई की जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार एमएसएमई के लिए स्थिरता पहलों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट या क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण पर विचार कर रही है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) शुभारंभ अर्थात दिनांक 28.04.2022 से दिनांक 18.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेड) प्रमाणन प्राप्त करने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की कुल संख्या 2,78,035 है। इसका राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-I** पर देखा जा सकता है।

(ख) एमएसएमई की सततता और प्रतिस्पर्धात्मकता पर जेड प्रमाणन के प्रभाव को प्रमाणन के लिए आवश्यक विभिन्न मूल्यांकन मापदंडों के अनुरूप होने के माध्यम से प्राप्त किया गया है। तथापि, सभी केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के लिए, स्कीम कार्यान्वयन के तीन वर्ष पूरे होने के बाद तृतीयक पक्ष के मूल्यांकन का प्रावधान है। यह मूल्यांकन स्कीम के प्रभाव का विवरण देता है। चूंकि, जेड स्कीम की शुरुआत अप्रैल, 2022 में की गई थी, इसलिए तृतीयक पक्ष का मूल्यांकन अप्रैल, 2025 के बाद किया जाना है।

(ग) जेड स्कीम में एमएसएमई की जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से छोटे उद्यमों के बीच, एमएसएमई मंत्रालय, कार्यान्वयन एजेंसी (भारतीय गुणवत्ता परिषद), औद्योगिक संघों और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पहलें की गई हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ जागरूकता कार्यक्रम (वर्चुअल और वास्तविक), पंजीकरण शिविर, राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएँ, ऑन-साइट सहायता, समाचार पत्र और रेडियो के माध्यम से विज्ञापन आदि शामिल हैं।

(घ) जेड स्कीम एमएसएमई को मूल्यांकन और प्रमाणन की तैयारी में सहायता देने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट मूल्यांकनकर्ताओं, परामर्शदाताओं और क्षेत्रीय मार्गदर्शन दस्तावेजों का उपयोग करके क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोण का अनुपालन करती है। उद्यम के अंतर्गत सभी विनिर्माण क्षेत्रों को जेड प्रमाणन के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

****

अनुबंध-I

दिनांक 24.03.2025 को उत्तरार्थ राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2647 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

शुभारंभ अर्थात दिनांक 28.04.2022 के बाद से दिनांक 18 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार जेड प्रमाणपत्रों की संख्या (राज्य-वार और वर्ष-वार):

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जेड प्रमाणन (2022-23)	जेड प्रमाणन (2023-24)	जेड प्रमाणन (2024-25)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2	0	0
2	आंध्र प्रदेश	19	5680	4109
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1
4	असम	11	1675	1039
5	बिहार	54	16017	4692
6	चंडीगढ़	0	682	22
7	छत्तीसगढ़	10	1924	763
8	दिल्ली	35	867	438
9	गोवा	7	10	4
10	गुजरात	125	38383	17720
11	हरियाणा	135	11207	3325
12	हिमाचल प्रदेश	96	914	820
13	जम्मू एवं कश्मीर	8	771	1816
14	झारखंड	26	1670	195
15	कर्नाटक	434	33869	12465
16	केरल	52	2419	928
17	लद्दाख	2	4	2
18	लक्षद्वीप	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	26	7359	4370
20	महाराष्ट्र	328	10278	8922
21	मणिपुर	2	1	1
22	मेघालय	0	1	1
23	मिजोरम	0	0	0
24	नागालैंड	2	0	27
25	ओडिशा	62	847	176
26	पुदुचेरी	10	170	46
27	पंजाब	597	9414	5513
28	राजस्थान	94	8299	8305
29	सिक्किम	0	1	0
30	तमिलनाडु	794	7559	1674
31	तेलंगाना	30	2435	2245
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	13	13	161
33	त्रिपुरा	0	229	36
34	उत्तर प्रदेश	89	9817	16626
35	उत्तराखंड	17	516	290
36	पश्चिम बंगाल	80	3286	1826
	सकल योग	**3,160**	**1,76,317**	**98,558**